भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5472

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

कोसी-मेची लिंक परियोजना की डीपीआर को स्वीकृति

5472. श्री गिरिधारी यादव:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोसी-मेची लिंक परियोजना, जो बिहार में बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्रीय वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के पास अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त डीपीआर को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना में महानंदा नदी बेसिन के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के विस्तार के लिए कोसी नदी के अधिशेष जल के एक हिस्से के विपथन की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) को इसके अंतिम हिस्से को मेची नदी तक विस्तारित किया जाएगा, ताकि बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियों को राज्य के भीतर एक साथ जोड़ा जा सके। लिंक परियोजना से खरीफ मौसम में परमान और मेची नदियों के बीच महानंदा बेसिन में लिंक नहर के नए कमांड मार्ग में 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले लाभान्वित होंगे।

कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा तैयार की गई तथा मार्च, 2014 में बिहार सरकार को भेज दी गई। सभी अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं। एनडब्ल्यूडीए द्वारा दिसंबर, 2022 में कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना की डीपीआर का अद्यतन कार्य भी पूरा कर लिया गया था और परियोजना को बाद में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा मार्च, 2024 में स्वीकार कर लिया गया था, जिसकी अनुमानित लागत वर्ष 2022-23 के मूल्य स्तर पर 6,282.32 करोड़ रुपये है।

मार्च, 2025 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जिसके कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य को 3,652.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

*****